Daily Current Affairs

Date : 10 June, 2026

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में 'पीएम स्वनिधि योजना' का क्रियान्वयन
2.	'पीएम कुसुम योजना' के तहत 'केन्द्रीय वित्तीय सहायता'
3.	प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप - 2026 (राजस्थान का प्रदर्शन)
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. ग्रीनफिट और अरावली फाउंडेशन द्वारा प्लॉग रन का आयोजन 2. कोटा में 500 थ्री-फेज विद्युत इंजनों की क्षमतायुक्त विद्युत लोको शेड 3. खेलो राजस्थान यूथ गेम्स 4. IPS परिस अनिल देशमुख 5. ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर अभियान 6. 800 वरिष्ठ नागरिकों को ₹75 लाख के सहायक उपकरण वितरित 7. 12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस - 2026
5.	राज्य वित्त आयोगों (SFCs) के लिए डेटासेट्स पर रिपोर्ट
6.	संवेदनशील वर्गों का समावेशी परिवर्तन
7.	ज्ञान भारतम मिशन
8.	खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)
9.	H-1B

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान परिदृश्य

राजस्थान में 'पीएम स्वनिधि योजना' का क्रियान्वयन

चर्चा में क्यों?

- 'पीएम स्वनिधि योजना' के तहत राजस्थान में 10 जून, 2026 तक पात्र आवेदकों में से 3,06,255 लाभार्थियों के लिए ₹439 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, जिसमें से 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को ₹428 करोड़ 93 लाख से अधिक की राशि का ऋण वितरित किया जा चुका है।

मुख्य बिन्दु:

- **राजस्थान में 'पीएम स्वनिधि योजना' (PM SVANidhi) का क्रियान्वयन :** स्वायत्त शासन विभाग द्वारा।
- राजस्थान में इस योजना की लगभग 34 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं, जबकि लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वंचित समुदायों से संबंधित हैं।

योजना के तहत सर्वाधिक आवेदकों वाले शीर्ष – 5 ज़िले:

संख्या	ज़िले का नाम	आवेदन
1.	जयपुर	60,000+
2.	जोधपुर	18000+
3.	बीकानेर	14068
4.	अजमेर	13165
5.	उदयपुर	10665

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

PM SVANidhi योजना:

- **लॉन्च :** 01 जून, 2020 को।
- **योजना की अवधि :** मार्च, 2030 तक।
- **पूरा नाम :** प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)
- **संबंधित मंत्रालय :** आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वयन।
- यह देश की पहली ऐसी सूक्ष्म वित्तीय योजना है, जो विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तैयार की गई है और जिसे केंद्र सरकार की क्रेडिट गारंटी का संरक्षण प्राप्त है।
- **ऋण :** योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिना किसी गारंटी के चरणबद्ध तरीके से ₹15000, ₹25,000 और ₹50,000 तक का कार्यशील पूँजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी पुनर्भुगतान अवधि क्रमश: 12 माह, 18 माह एवं 36 माह हैं।
- **ब्याज अनुदान :** पीएम स्वनिधि योजना समय पर और शीघ्र ऋण चुकाने को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **अतिरिक्त प्रोत्साहन :** योजना के अंतर्गत दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले विक्रेता ₹30,000 तक की सीमा वाले यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होते हैं। साथ ही, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को ₹1,600 तक का कैशबैक दिया जाता है।

योजना का उद्देश्य:

- शहरी क्षेत्र के जरूरतमन्द एवं असहाय परिवारों को सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
- लघु व्यवसाय और उद्यमों में पूँजी प्रवाह की वृद्धि करना।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

पात्रता (राजस्थान में):

- आयु सीमा 18 से 60 वर्ष हो और राजस्थान का मूल निवासी हो।
- आवेदक के पास स्थानीय शहरी क्षेत्र का जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी के पास कार्य का सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा-पत्र हो।
- **ऋणदात्री संस्थाएँ :** राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा RBI द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल बैंक।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

‘पीएम कुसुम योजना’ के तहत ‘केन्द्रीय वित्तीय सहायता’

चर्चा में क्यों?

- पीएम-कुसम योजना के कम्पोनेंट-सी में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले प्रदेश के 553 ऊर्जादाताओं के लिए भारत सरकार ने ₹531 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) स्वीकृत की।

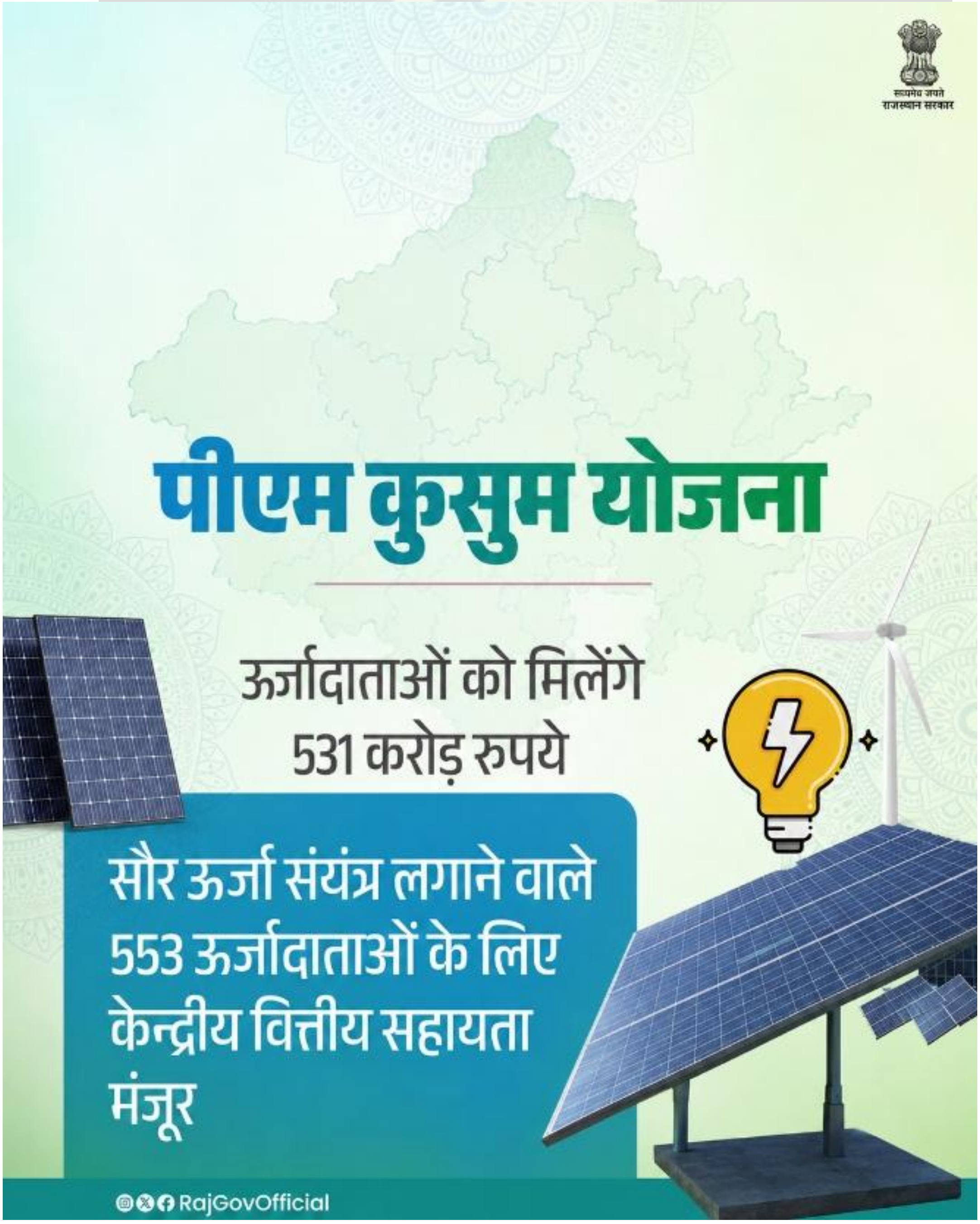

मुख्य बिन्दु:

- इस राशि का भुगतान 'अजमेर एवं जोधपुर' विद्युत वितरण निगम द्वारा संबंधित ऊर्जादाताओं के बैंक खातों में किया जाएगा।
- केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 429 मेगावाट के संयंत्र लगाने वाले जोधपुर विद्युत वितरण निगम के 432 ऊर्जादाताओं को ₹379.41 करोड़ रुपए तथा 169 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने वाले अजमेर डिस्कॉम के 121 सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए 151.21 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है।
- अब तक जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों द्वारा कुल ₹1012 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के क्लेम केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
- **कम्पोनेंट-सी में 3371 मेगावाट (MW) की परियोजनाएँ :** प्रदेश में कम्पोनेंट-सी के अन्तर्गत 3371 मेगावाट क्षमता की 1312 परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें जोधपुर डिस्कॉम में 2647 मेगावाट, अजमेर डिस्कॉम में 373 मेगावाट तथा जयपुर डिस्कॉम में 352 के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

पीएम कुसुम:

- **शुरुआत :** मार्च, 2019
- **पूरा नाम :** प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान।
- **नोडल मंत्रालय :** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- **उद्देश्य :** किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों से विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

योजना के तीन घटक (Components):

कम्पोनेन्ट-ए:

- 500 किलोवाट (kW) से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले व्यक्तिगत संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से 10,000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना करना।
- ट्रांसमिशन लाइनों की उच्च लागत और नुकसान से बचने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों को अधिसूचित सब-स्टेशनों के पाँच किलोमीटर के दायरे में स्थापित करना।
- उत्पादित विद्युत की खरीद स्थानीय डिस्कॉम (Distribution Company) द्वारा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) द्वारा निर्धारित पूर्व-निर्धारित टैरिफ पर की जाती है।
- नोट : राजस्थान में कंपोनेंट-ए का कार्यान्वयन प्रारंभ में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) द्वारा किया जा रहा था, जिसे 23 जुलाई, 2024 को राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान डिस्कॉम्स को हस्तांतरित कर दिया गया।

कम्पोनेन्ट-बी:

- 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना।
- इस घटक के तहत 3 से 10 हॉर्सपावर (HP) तक के स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7.5 हॉर्सपावर तक के पंपों के लिए अधिकतम अनुदान देय है।
- जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और जो डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर हैं, वे इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप प्रणाली स्थापित करने के पात्र हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत किसानों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। शेष 60 प्रतिशत भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बराबर-बराबर 30-30 प्रतिशत दिया जाता है।

- 40 प्रतिशत में से किसान बैंक से 30 प्रतिशत तक ऋण ले सकता है और शेष 10 प्रतिशत किसानों को देना होगा।
- योजना के कम्पोनेंट-बी का क्रियान्वयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

कम्पोनेन्ट-सी (फीडर लेवल सोलराईजेशन)

- योजना के घटक-सी में सब स्टेशन से 5 किमी के दायरे में अनुपजाऊ भूमि पर 5 मेगावाट तक के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। प्लांट लगाकर सम्पूर्ण कृषि फीडर का सौरीकरण करने वाले सौर ऊर्जा उत्पादकों को भारत सरकार संयंत्र की लागत एवं क्षमता के आधार पर 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके लिए अधिकतम सहायता 1.05 करोड़ रूपए प्रति मेगावाट निर्धारित है।
- मंत्रालय ने 4,00,000 पम्प सेटों का सोलराईजेशन करने का लक्ष्य स्वीकृत किया है।

UTKARSH CIVIL SERVICES

प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप - 2026 (राजस्थान का प्रदर्शन)

चर्चा में क्यों?

- अहमदाबाद में आयोजित 'प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप – 2026' में राजस्थान ने 6 स्वर्ण पदक जीते।

मुख्य बिन्दु:

- **भारत का प्रदर्शन :** चैंपियनशिप में 114 पदक (102 स्वर्ण, 9 रजत, 3 कांस्य) जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान।
- **आयोजन स्थल :** 4 से 8 जून, 2026 तक अहमदाबाद के एका एरिना में।
- **आयोजन संस्था :** योगासन भारत महासंघ।
- **शुभंकर :** 'वीर द लायन'।

राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता:

क्रम	पदक विजेता का नाम	वर्ग
1.	ऋतिक बिश्नोई (जोधपुर)	जूनियर वर्ग की आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक।
2.	देवांशी शर्मा (जयपुर)	सीनियर-B हैंड बैलेंस (इंडिविजुअल) में स्वर्ण पदक।
3.	गायत्री चौधरी (मांडोता, सीकर)	सीनियर-C महिला बैक/बैलेंस बेंडिंग इंडिविजुअल में स्वर्ण पदक।
4.	आर्यांशी स्वामी (श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर)	दो स्वर्ण पदक। आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट में स्वर्ण पदक।
5.	अर्जुन परिहार	आर्टिस्टिक पेयर में स्वर्ण पदक।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**ग्रीनफिट और अरावली फाउंडेशन द्वारा प्लॉग रन का आयोजन** ■ विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर में ग्रीनफिट और अरावली फाउंडेशन द्वारा प्लॉग रन (दौड़ते या जॉगिंग करते हुए कचरा उठाना) का आयोजन किया गया।
2.	**कोटा में 500 थ्री-फेज विद्युत इंजनों की क्षमतायुक्त विद्युत लोको शेड** ■ कोटा के काला तालाब क्षेत्र में कोटा रेल मंडल द्वारा 500 थ्री-फेज विद्युत इंजनों की क्षमतायुक्त विद्युत लोको शेड का निर्माण किया जाएगा। ■ क्षेत्रफल : लगभग 8 हेक्टेयर। ■ प्रोजेक्ट नोडल : कोटा मण्डल, पश्चिम मध्य रेलवे (WCR)
3.	**खेलो राजस्थान यूथ गेम्स** ■ राजस्थान सरकार द्वारा 'खेलो इंडिया' की तर्ज पर 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' की शुरुआत की गई है, जिसके आयोजन के लिए राज्य सरकार ने ₹50 करोड़ के बजट की घोषणा की है। ■ इन खेलों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय खिलाड़ियों को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच प्रदान करना है।
4.	**IPS परिस अनिल देशमुख** ■ राजस्थान कैडर के 2010 बैच के IPS अधिकारी परिस अनिल देशमुख को केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल (BSF) में पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर नियुक्त किया गया है। ■ केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, उन्हें 5 वर्ष के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर इस पद के लिए मंजूरी दी गई है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

5.	**ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर अभियान** ■ राजस्थान सरकार द्वारा आमजन की स्थानीय समस्याओं के समाधान और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 12 जून से 15 जुलाई, 2026 तक 'ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर अभियान' का आयोजन किया जा रहा है। ■ इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को सीधे जनता के बीच लाकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है।
6.	**800 वरिष्ठ नागरिकों को ₹75 लाख के सहायक उपकरण वितरित** ■ हाल ही में, चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO) द्वारा 800 वरिष्ठ नागरिकों को ₹75 लाख मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए।
7.	**12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस - 2026** ■ **राज्य स्तरीय कार्यक्रम :** 21 जून, 2026 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। ■ **वर्ष 2026 की थीम :** 'Yoga for Healthy Ageing' (स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग)।

आर्थिक घटनाक्रम

राज्य वित्त आयोगों (SFCs) के लिए डेटासेट्स पर रिपोर्ट

[PIB]

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य वित्त आयोगों (SFCs) को सशक्त बनाने के लिए एक सुदृढ़ 'सूचना संरचना' बनाने की सिफारिश की है।
- इसका उद्देश्य डेटा-आधारित वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर शासन-संरचना को प्रभावी बनाना है।

मुख्य बिन्दु:

राज्य वित्त आयोगों (SFCs)

- **संवैधानिक प्रावधान:** राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत गठित संवैधानिक निकाय हैं।
- **मुख्य कार्य:** इनका मुख्य कार्य राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच राज्य के राजस्वों के वितरण की सिफारिश करना है।

राज्य वित्त आयोगों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **अलग-अलग डेटा संग्रह:** डेटा अलग-अलग संगठनों के पास होने और इन संगठनों में समन्वय न होने के कारण स्थानीय निकायों के प्रदर्शन की समग्र जानकारी नहीं मिल पाती।
- **क्षेत्रकवार डेटा का अभाव:** पंचायत स्तर और क्षेत्रक-वार व्ययों के सटीक डेटा की कमी के कारण स्थानीय निकायों के प्रदर्शन-आधारित वित्तीय विश्लेषण करना मुश्किल होता है।
- **गैर-मानक लेखा:** राज्यों में अलग-अलग लेखा प्रणालियाँ होने और समेकित वित्तीय विवरणों की कमी के कारण राज्यों के बीच तुलना करना कठिन हो जाता है।

- **क्षमता की कमी:** जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण डिजिटल रूप में डेटा का रखरखाव और प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाते।
- **अन्य:** राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी की जाती है और वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण में भी कमी।

प्रमुख सिफारिशें

- **प्रदर्शन का लेखा-परीक्षण (ऑडिट):** राज्यों में 73वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लेखा-परीक्षण किया जाना चाहिए।
- **स्थायी राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ:** राज्यों को वित्तीय डेटा को लगातार अद्यतन रखने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने चाहिए।
- **मानकीकृत लेखा:** स्थानीय निकायों को होने वाले हस्तांतरण के लिए एक समान लेखा प्रणाली लागू की जाएं और एक साझा रिपोर्टिंग प्रारूप अपनाया जाए, ताकि राज्यों के बीच एकरूपता स्थापित हो सके और उनके डेटा की आपस में तुलना की जा सके।
- **व्यवस्थित प्रदर्शन संकेतक:** 'पंचायत उन्नति सूचकांक' के मानकों को "आवश्यकता (Needs)", "प्रदर्शन (Performance)" और "समानता (Equity)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए, ताकि वित्तीय आवंटन के फार्मूले को और अधिक सटीक बनाया जा सके।

संवेदनशील वर्गों का समावेशी परिवर्तन

[PIB]

चर्चा में क्यों?

- पिछले एक दशक में, भारत ने कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से एक समावेशी परिवर्तन देखा है, जिससे अभाव में काफी कमी आई है और कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

मुख्य बिन्दु:

समावेशी परिवर्तन

- समावेशी परिवर्तन से तात्पर्य एक ऐसी विकास प्रक्रिया से है जो यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सार्वजनिक नीतियों के लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समूहों तक पहुँचे।
- इसका उद्देश्य न केवल आय के स्तर में सुधार करना है, बल्कि बुनियादी सेवाओं, अवसरों और मानवीय क्षमताओं तक पहुंच में भी सुधार करना है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके।

समावेशी परिवर्तन के लिए पहल

गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा:

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
- वन नेशन वन राशन कार्ड प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता में सुधार किया है और भ्रष्टाचार को कम किया है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

वित्तीय समावेशन:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से 58 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हुई है।
- पीएम मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करती है।
- UPI और डिजिटल भुगतान ने वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेनदेन को सुगम बनाया है।

स्वास्थ्य सेवा और पोषण:

- आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और निर्बाध स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ावा देता है।
- इंद्रधनुष मिशन और मातृ स्वास्थ्य योजनाएँ शिशु और मातृ स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार लाती हैं।

जल, स्वच्छता और आवास:

- जल जीवन मिशन घरों में नल के पानी के सुचारू कनेक्शन उपलब्ध कराता है।
- स्वच्छ भारत मिशन ने लगभग सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज हासिल कर लिया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देती है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

महिला सशक्तिकरण:

- **पीएम उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करती है।**
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बालिका की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।**
- **DAY-NRLM, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी पहलें महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम को प्रोत्साहित करती हैं।**

आजीविका और रोजगार सृजन:

- **विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन मजदूरी आधारित रोजगार और ग्रामीण संपत्ति सृजन प्रदान करता है।**
- **पीएम स्वनिधि बिना गारंटी के ऋण देकर स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करती है।**
- **प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कार्यक्रम पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाता है।**

जनजातीय विकास

- **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान समग्र आदिवासी विकास पर केंद्रित है।**
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच में सुधार करते हैं।**

समावेशी परिवर्तन में हासिल की गई प्रगति

- **गरीबी और अभाव: बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई, जो 17.89 प्रतिशत अंकों की कमी को दर्शाती है।**
  - **इस अवधि के दौरान लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।**

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **जल, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं:** जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी की उपलब्धता 2019 में 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर मई 2026 में 15.84 करोड़ घरों तक पहुंच गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के 81.87% घरों को कवर करती है।
  - ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% से बढ़कर 2019 में 100% हो गया।
- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार:** मातृ मृत्यु दर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 (2014-16) से घटकर 88 (2021-23) हो गई है।

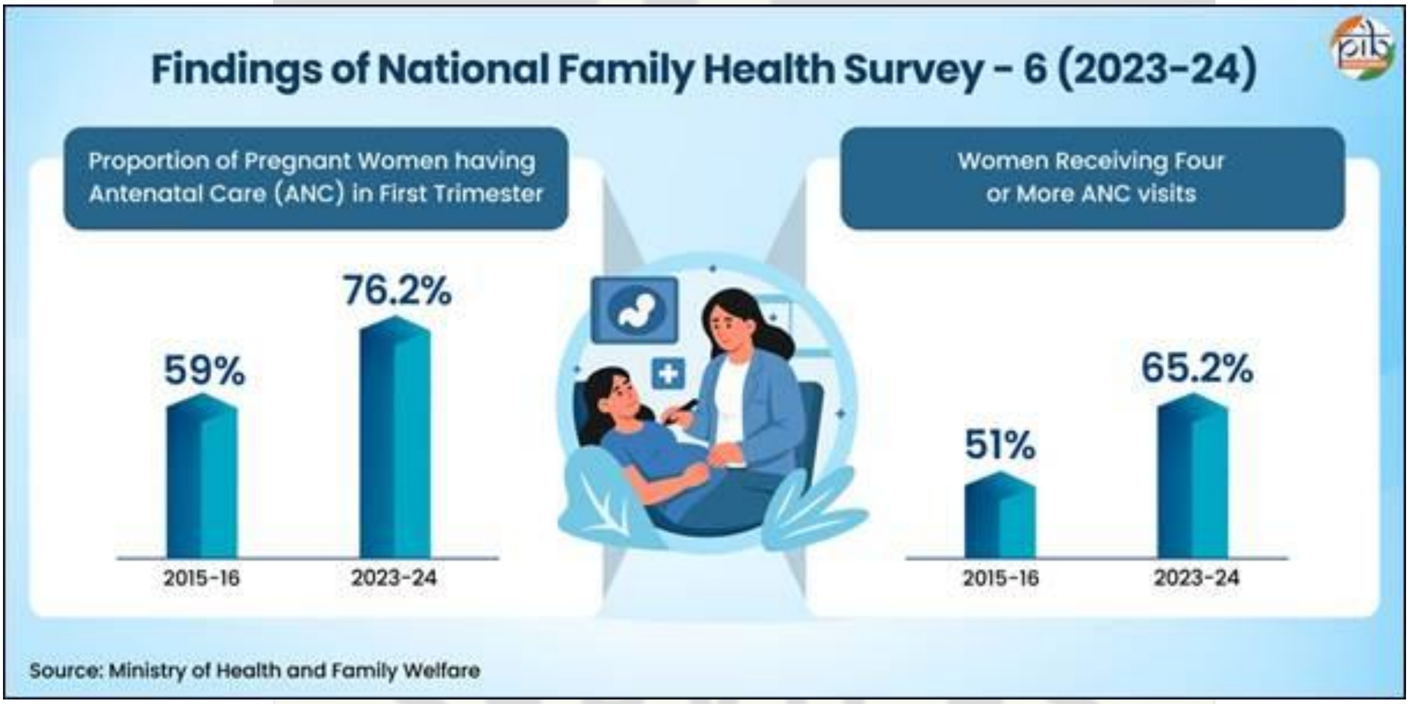

- **स्वच्छ ऊर्जा और बिजली:** पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.57 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत आपूर्ति 2014 में 12.5 घंटे/दिन से बढ़कर 2025 में 22.6 घंटे/दिन हो गई।
- **आजीविका और महिला नेतृत्व वाला विकास:** DAY-NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या 2.37 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है।

Viksit Bharat

Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)

Indicator	FY 2006-14	FY 2014-25	% Increase
Persondays generated (crore)	1,660	3,036.7	~83%
Central funds released (₹ crore)	2,13,220	7,81,635.65	~267%
Works completed (lakh)	153	809.05	~429%

Source: Ministry of Rural Development

चुनौतियाँ

- **क्षेत्रीय असमानताओं का निरंतर बने रहना:** राज्यों, जिलों और जनजातीय क्षेत्रों में विकास के परिणाम असमान बने हुए हैं।
- **सार्वजनिक सेवाओं में गुणवत्ता की कमी:** पहुंच में सुधार हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता में अभी भी असंगति बनी हुई है।
- **आय संबंधी असुरक्षा:** श्रम बाजार में अनौपचारिक रोजगार का दबदबा बना हुआ है और रोजगार सृजन भी कार्यबल के विस्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है।
- **पोषण संबंधी चुनौतियाँ:** बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और बौनापन अभी भी महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय बने हुए हैं।
- **डिजिटल विभाजन:** इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता में अंतर अभी भी बना हुआ है, खासकर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में।
- **सामाजिक बहिष्कार:** प्रवासी, शहरी बेघर, बुजुर्ग नागरिक और विकलांग व्यक्ति सहित कुछ कमजोर समूहों को कल्याणकारी लाभों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **राजकोषीय स्थिरता:** कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं के विस्तार के लिए निरंतर राजकोषीय संसाधनों और कुशल लक्ष्यीकरण की आवश्यकता होती है।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

ज्ञान भारतम मिशन

[AIR]

चर्चा में क्यों?

- ज्ञान भारतम सर्वेक्षण के तहत पूरे भारत में एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को सूचीबद्ध किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

ज्ञान भारतम मिशन

- **उद्देश्य:** यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है।
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय
- **फोकस:** भारत की पांडुलिपि विरासत का डिजिटल माध्यम में संरक्षण, सूचीकरण और साझा करना।
- **शामिल पांडुलिपियां:** इनमें ताड़पत्र, भोजपत्र और कागज पर लिखी संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं की पांडुलिपियां शामिल हैं।
- **पांच स्तंभ:** सर्वेक्षण और सूचीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण, अनुवाद और अनुसंधान एवं आउटरीच।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)

[THE HINDU]

चर्चा में क्यों?

- काबिल (KABIL) ने अर्जेंटीना में पांच महत्त्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिज ब्लॉक्स का अधिग्रहण किया।
- अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया मिलकर "लिथियम ट्रायंगल" का निर्माण करते हैं, जिनके पास विश्व का आधे से अधिक लिथियम संसाधन है।
- अर्जेंटीना के पास विश्व के तीसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार है तथा चौथा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है।

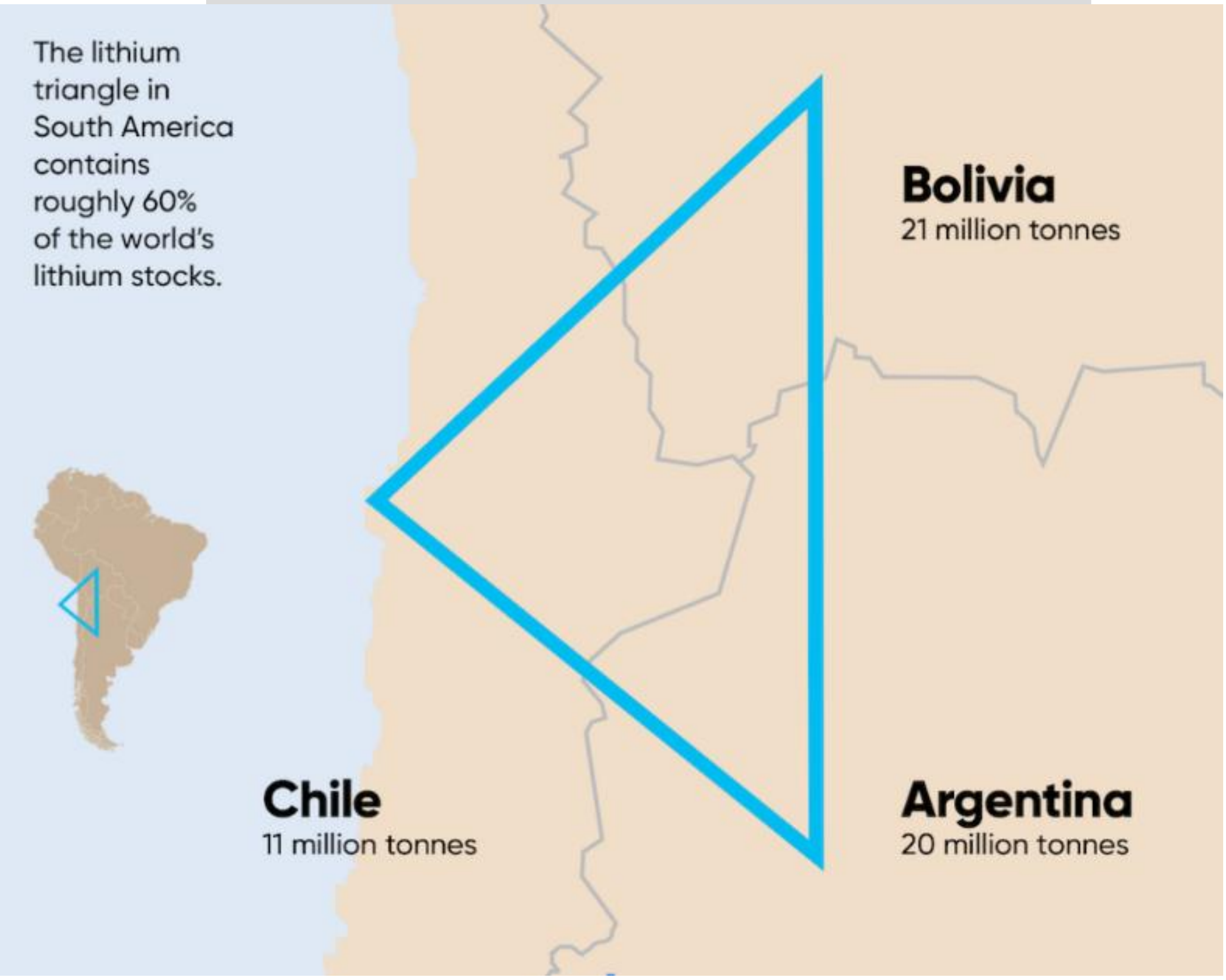

मुख्य बिन्दु:

काबिल (KABIL)

- **स्थापना:** वर्ष 2019 में केंद्रीय खान मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित
- **संयुक्त उद्यम संरचना:** NALCO, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) और MECL द्वारा 40:30:30 शेयरधारिता के अनुपात में गठित।
- **उद्देश्य:** महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करना तथा भारत की खनिज सुरक्षा एवं आपूर्ति-श्रृंखला की निरंतरता सुनिश्चित करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

H-1B

[TIMES OF INDIA]

चर्चा में क्यों?

- एक अमेरिकी संघीय न्यायालय ने H-1B वीजा शुल्क को बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने के निर्णय को गैर-कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया।

मुख्य बिन्दु:

H-1B वीज़ा

- एच-1बी वीज़ा एक गैर-आप्रवासी वर्क-वीजा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को ऐसे विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके कार्य के लिए विशेष ज्ञान तथा कम से कम स्नातक या समकक्ष योग्यता आवश्यक होती है।
- **पात्र क्षेत्रक:** सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, वित्त, अनुसंधान, शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, आदि।
- **अवधि:** शुरुआत में यह 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है (और कुछ ग्रीन-कार्ड प्रक्रिया वाले मामलों में इससे भी अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है)।
- **भारत का महत्त्व:** भारतीय नागरिक H-1B कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। इस वीजा को प्राप्त करने वालों में भारतीय सर्वाधिक हैं।